

संख्या-59/53-1-2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,  
दुग्धशाला विकास, उ०प्र०,  
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक-20.02.2023 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-583/दुग्ध-4/दुग्ध नीति-2022/2025-26, दिनांक-20.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-104/53-1-2023, दिनांक-20.02.2023 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक-20.02.2023 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक-20.02.2023 में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

प्रस्तर	वर्तमान में विद्यमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान/नवीन प्राविधान
2-प्रस्तावों की पात्रता	उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रभावी अवधि में स्थापित होने वाली इकाईयाँ इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान, रियायतें व सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगी।	उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रभावी अवधि में स्थापित होने वाली इकाईयाँ इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान, रियायतें व सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगी। परियोजना हेतु ऋण स्वीकृति पत्र तथा अनुदान हेतु क्लेम किये गये तकनीकी सिविल कार्य, प्लांट मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स से सम्बन्धित

									बिल/इनवाइस भी नीति के प्रभावी अवधि के होने चाहिये।
5 (iv)									<p>सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना।</p> <p>सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना।</p> <p>दिनांक 21-03-2025 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की परिभाषा मान्य होगी। यदि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नवीन अधिसूचना जारी होती है तो उक्त नवीन अधिसूचना के अनुसार मान्य होगी।</p>
6-पात्र/ अपात्र घटक	क्र 0 सं 0	वि व र ण	पात्र घटक	अपात्र घटक	क्र 0 सं 0	वि व र ण	पात्र घटक	अपात्र घटक	
	2	म शी न री	<p>उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद की समस्त प्रक्रियाओं से सम्बन्धित उपकरण एवं मशीनरी पात्र घटक के अन्तर्गत आयेंगे। उदाहरणार्थ-</p> <p>क-दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित-</p> <p>(1) आटोमेशन, मिक्सिंग, सेपरेशन, स्टेन्डर्डाइजेशन, शुगर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एण्ड सेनेटाइजेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लैरिफिकेशन, फोर्टीफाईंग आदि।</p> <p>(2) पाथुराइजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, ड्राई</p>	<p>प्ला ण्ट ए वं म शीनरी में नि म्नलि खित को अ पात्र घटक में शा मिल किया जाये गा:- (1) ई धन/ तेल आदि</p>	2	म शी न री	<p>उद्योगों में दुग्ध अवशीतन व दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद की समस्त प्रक्रियाओं से सम्बन्धित उपकरण एवं मशीनरी पात्र घटक के अन्तर्गत आयेंगी। उदाहरणार्थ-</p> <p>क-दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित-</p> <p>(1) आटोमेशन, मिक्सिंग, सेपरेशन, स्टेन्डर्डाइजेशन, शुगर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एण्ड सेनेटाइजेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस</p>	<p>प्ला ण्ट. ए वं म शीनरी में नि म्नलि खित को अ पात्र घटक में शा मिल किया जाये गा:- (1) ई धन/ तेल आदि उपभो</p>	

		<p>ग, स्टरलाइजेशन, कन्सन्ट्रेशन आदि।</p> <p>(3) कैनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, लेबलिंग, फिलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि।</p> <p>(4) फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि।</p> <p>(5) कन्ट्रोल्ड टेम्प्रेचर, ट्रान्सपोर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।</p> <p>(6) प्लांट के अन्दर अन्य समस्त प्रसंस्करण/परीक्षण/यातायात/भण्डार सुविधाएं जो कि मूल्य संवर्धन एवं शेल्फ लाईफ बढ़ाने से सम्बन्धित हों, पात्र होंगे।</p> <p>ख-पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद से सम्बन्धित -पेलेट मिल, मिक्सर, शीरा भंडारण टैंक, बॉयलर, कन्वेयर सिस्टम, स्काडा आधारित स्वचालन, अनाज भंडारण साइलो आदि के साथ पशु आहार निर्माण से सम्बन्धित निर्माण संयंत्र आदि पात्र होंगे।</p> <p>ग- तकनीकी उन्नयन-तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।</p> <p>घ-ट्रेसबिलिटी एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण-ट्रेसबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल</p>	<p>उपभोग की वस्तुयें एवं भण्डार सामग्री।</p> <p>(2) कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण।</p> <p>(3) परिवहन वाहन।</p> <p>(4) उपयोग की गयी/पुरानी मशीनें / मरम्मत की हुई मशीनरी।</p> <p>(5) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और</p>	<p>, क्लैरिफिकेशन, फोर्टीफाइंग आदि।</p> <p>(2) पाश्चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, इवैपोरेशन, ड्राइंग, स्टरलाइजेशन, कन्सन्ट्रेशन आदि।</p> <p>(3) कैनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, लेबलिंग, फिलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि।</p> <p>(4) फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि।</p> <p>(5) कन्ट्रोल्ड टेम्प्रेचर, ट्रान्सपोर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।</p> <p>(6) इकाई के अन्दर अन्य समस्त प्रसंस्करण/परीक्षण/यातायात/भण्डार सुविधाएं जो कि मूल्य संवर्धन एवं शेल्फ लाईफ बढ़ाने से सम्बन्धित हों, पात्र होंगे।</p> <p>(7) इंस्टॉलेशन (स्थापना) और कमीशनिंग (प्रचालन) चार्ज ख-पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद से सम्बन्धित-पेलेट मिल, मिक्सर, शीरा भंडारण टैंक, बॉयलर, कन्वेयर सिस्टम,</p>	<p>ग की वस्तुयें एवं भण्डार सामग्री।</p> <p>(2) कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण।</p> <p>(3) परिवहन वाहन।</p> <p>(4) उपयोग की गयी/पुरानी मशीनें / मरम्मत की हुई मशीनरी।</p> <p>(5) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और</p>
--	--	---	--	---	--

		<p>ल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चैन के अतिरिक्त) इत्यादि पात्र होंगे।</p> <p>ड.-कोल्ड चैन की स्थापना -</p> <p>रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि से सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।</p>	<p>परिवहन शुल्क।</p> <p>(6) मशीनरी की पेंटिंग का व्यय।</p> <p>(7) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सम्बन्धित उपकरण।</p> <p>(8) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।</p> <p>(9) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।</p>		<p>स्काडा आधारित स्वचालन, अनाज भंडारण साइलो आदि के साथ पशु आहार निर्माण से सम्बन्धित निर्माण संयंत्र तथा परीक्षण संयंत्र आदि पात्र होंगे।</p> <p>ग- तकनीकी उन्नयन- तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।</p> <p>घ- ट्रेसिबिलिटी एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण- डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसिबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, विलेज लेवल कलेक्सन सेंटर हेतु क्रय की गयी मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स (कोल्ड चैन के अतिरिक्त) इत्यादि पात्र होंगे।</p> <p>ड.कोल्ड चैन की स्थापना- दुग्ध अवशीतन केन्द्र/कोल्ड रूम की स्थापना, रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आ</p>	<p>परिवहन शुल्क।</p> <p>(6) मशीनरी की पेंटिंग का व्यय।</p> <p>(7) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सम्बन्धित उपकरण।</p> <p>(8) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।</p> <p>(9) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।</p>
--	--	---	---	--	---	---

							इसक्रीम ट्राली/डीप फ्रीजर इत्यादिकोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना हेतु क्रय की गयी मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स से सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।
7:- प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं सुविधाएं निम्नवत् होंगी:-							
7.1 पूंजीगत निवेश अनुदान -	प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम ₹0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	(क) प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम ₹0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम ₹0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (ग) विद्यमान डेयरी प्लान्ट में आधुनिक तकनीकी उन्नयन अथवा स्टार्ट-अप जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना पर प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम ₹0 2.50 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (घ) डेयरी प्लान्ट के बाहर फील्ड में ट्रेसिबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट (ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट)/विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर हेतु क्रय की गई मशीनरी, तथा स्पेयर					

		<p>पाटर्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम रु 0 1.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (वैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज अन्तर्गत)</p> <p>(ड.) रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली/डीप फ्रीजर इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय तथा चिलिंग प्लांट की स्थापना /कोल्डरूम हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पाटर्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम रु0 1.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज अन्तर्गत)</p> <p>(च) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण (मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पाटर्स की लागत पर 35 प्रतिशत, अधिकतम रु0 2.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>(छ) सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले FSSAI विनियमों के अनुसार मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे:-चीज, आइसक्रीम, पनीर, छेना, खोया, कुल्फी इत्यादि का विनिर्माण करने के लिए सूक्ष्म श्रेणी की इकाई की स्थापना हेतु क्रय की गई प्लान्ट मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान अधिकतम रु0 50.00 लाख की सीमा तक उपलब्ध कराया जायेगा।</p>
7.2 ब्याज उपादान -	<p>(क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना</p> <p>नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पाटर्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु</p>	विलोपित।

	<p>अधिकतम रू0 10.00 करोड की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 7.50 करोड की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ग) दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन विद्यमान डेयरी प्लान्ट में तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(घ) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसेबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटो मेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चैन के अतिरिक्त) हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ङ.) कोल्ड चैन की स्थापना रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि कोल्ड चैन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(च) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान</p>	
--	--	--

	<p>मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रु0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(छ) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान</p> <p>मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रु0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ज) मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान</p> <p>सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे: -चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रु0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p>	
<p>7.6 विद्युत शुल्क (अधिभार )</p>	<p>नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी।</p>	<p>नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी। विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति पशुआहार एवं पशु पोषण निर्माणशाला इकाई की स्थापना अथवा दुग्ध अवशीतन केन्द्र इत्यादि अन्य मदों की इकाईयों के लिये मान्य नहीं होगी।</p>

7.7- स्टाम्प शुल्क	उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का आंकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।	उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा न्यूनतम 15 वर्ष की लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का आंकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।
7.8- आरक्षित भूमि के श्रेणी परिवर्तन शुल्क में छूट	-	इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले परियोजना स्थल के मध्य आने वाली आरक्षित श्रेणी की भूमियाँ जैसे चकरोड आदि का श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा तथा आरक्षित श्रेणी की भूमि चकरोड, नाली इत्यादि के विनिमय के फलस्वरूप दी जाने वाली भूमि पर चकरोड, नाली इत्यादि का निर्माण प्रश्रुगत निवेशक/संस्था द्वारा स्वयं कराकर दिया जायेगा ।
7.9 भू- उपयोग परिवर्तन एवं बाह्य विकास शुल्क में छूट-	-	(1) इस नीति के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिये कृषि भूमि में स्थापित होने की स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी ।  (11) इस नीति के अंतर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को बाह्य विकास शुल्क की दर में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी ।

<p><b>7.10-बि</b> जली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रोत्साहन प्राविधान।</p>		<p>1-औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अवस्थित डेयरी से संबंधित इकाइयों/चिलिंग प्लांट/बीएमसी आदि को 75 के0वी0ए0 तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान सौर ऊर्जा परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत होगा और यह महिलाओं के स्वामित्व और संचालन वाली इकाइयों के लिए 90 प्रतिशत होगा।</p> <p>2-ऐसी इकाइयां, जिनमें महिलाओं की इक्विटी/शेयरधारिता न्यूनतम 51 प्रतिशत हो, ही महिला स्वामित्व एवं उनके द्वारा संचालित मान्य होगी।</p>
<p><b>11-नीति</b> के अन्तर्गत विस्तारित/ तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित आवेदन किये जाने पर संस्थान/प्लांट का पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन तथा पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन -</p>	<p>दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए तथा दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाइयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) एवं दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन करायें बिना आवेदक/संस्था द्वारा विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p>विस्तारीकरण/तकनीकी उन्नयन के प्रकरण में पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन करायें जाने हेतु विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) के निम्नवत अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-</p>	<p>दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित इकाइयों को पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन करने से पूर्व इकाई की वर्तमान क्षमता/स्थिति के आंकलन हेतु पोर्टल पर सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0), स्वीकृत टर्म लोन तथा बैंक अप्रैजल रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा।</p> <p>आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। विभागीय निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संस्था को परियोजना के विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किया जायेगा।</p> <p>विस्तारीकरण/तकनीकी उन्नयन के प्रकरण में पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन करायें जाने हेतु विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) के निम्नवत अध्यक्ष/</p>

	<p>1- सम्बन्धित मण्डल के दुग्धशाला विकास अधिकारी - अध्यक्ष</p> <p>2- सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी - सदस्य</p> <p>3- सम्बन्धित आवेदक/संस्था के प्रतिनिधि - सदस्य</p>	<p>सदस्य होंगे:-</p> <p>1- सम्बन्धित मण्डल के दुग्धशाला विकास अधिकारी - अध्यक्ष</p> <p>2- सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी- सदस्य</p> <p>3- सम्बन्धित आवेदक/संस्था के प्रतिनिधि - सदस्य</p> <p>विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है। विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण/ तकनीकी उन्नयन का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।</p>
<p>12- पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन</p>	<p>(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना से सम्बन्धित इकाईयों, पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासंभव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व करेंगे। पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।</p> <p>(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित इकाईयों को पूंजीगत अनुदान के लिए अपना आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्व गामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-ए) पर समस्त आ</p>	<p>नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना, नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना, दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी की स्थापना, कोल्ड चैन की स्थापना तथा मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयां, पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासंभव व्यावसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व करेंगे। पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 एवं 2 में उल्लिखित है।</p>

	<p>वश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।</p> <p>विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन प्रस्तर-11 में प्राविधानित विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0 टी0) द्वारा किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।</p>	
<p>12.1 ब्याज उपादान हेतु आवेदन</p>	<p>(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना, नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना, दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी की स्थापना, कोल्ड चेन की स्थापना तथा मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथा सम्भव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व किये जायेंगे। ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।</p> <p>(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित इकाईयों द्वारा आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्ज</p>	<p>विलोपित</p>

	<p>र-बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।</p> <p>दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादन विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण तथा दुग्धशाला के अन्दर तक नौकी उन्नयन की स्थापना से पूर्व सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p>(iii) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु ब्याज उपादान प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-बी/एनेक्जर-बीबी) (जो लागू हो) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1/अनुलग्नक-2 में उल्लिखित है।</p>	
<p>12.3 बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रोत्साहन हेतु आवेदन</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अवस्थित डेयरी से संबंधित इकाईयों/चिलिंग प्लांट/बीएमसी आदि को 75 केवी0ए0 तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर अनुदान हेतु आवेदन पोर्टल पर परियोजना स्थापित करने से पूर्व करेंगे। सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रोत्साहन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-2 में उल्लिखित है।</p> <p>बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रोत्साहन हेतु आवेदन से सम्बन्धित इकाईयों की यथास्थिति/विद्युत भार का सत्यापन सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, 50प्र0 के स्तर से विगत 03 माह (क्रमागत) के बिल के साथ प्राप्त किये जायेंगे, जिस पर सम्बन्धित जनपद के दुग्धशाला विभाग के जनपदीय अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के स्तर से प्रतिह</p>

		<p>स्ताक्षरित कराकर आॅनलाइन पोर्टल पर संस्था/इकाई द्वारा अपलोड किया जायेगा।</p> <p>1. net meter युक्त on-grid सौर ऊर्जा संयंत्रों, off-grid सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं net meterin g आधारित battery backup सहित hybrid सौर ऊर्जा संयंत्रों, तीनों प्रकार के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर अनुदान अनुमन्य होगा।</p> <p>2. अनुदान हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त solar panels एवं अन्य उपकरणों की अनुमन्य दरों का आकलन UP NEDA से प्राप्त नवीनतम अनुमन्य दरों के आधार पर किया जाएगा।</p> <p>3. सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त solar panels एवं अन्य उपकरणों की अनुमन्यता के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नवीनतम प्रचलित शासनादेशों का पालन किया जायेगा।</p>
<p>13-नीति के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त किये जाने से पूर्व संस्थान का भौतिक/स्थलीय सत्यापन</p>	<p>सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुदान/वित्तीय सहायता का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने, समस्त वांछित अभिलेख प्राप्त होने तथा संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) का भौतिक/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता अवमुक्त करने की नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत् अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-</p> <p>1-सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि (अपर जिलाधिकारी से अनिम्न हो) -अध्यक्ष</p> <p>2-सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी -सदस्य</p> <p>3- सम्बन्धित ऋण प्रदाता बैंक के प्रबन्धक -सदस्य</p> <p>प्रोत्साहन का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन/उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद किया जायेगा। अनुदान की धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के टर्मलोन खाते में जमा किया जायेगा।</p>	<p>उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (एस०एल०ई०सी०) द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त अनुमन्य धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों/शर्तों के अधीन स्वीकृति पत्र (Letter of sanction) जारी किया जायेगा।</p> <p>सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुदान/वित्तीय सहायता का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने, समस्त वांछित अभिलेख प्राप्त होने तथा संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) का भौतिक/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता अवमुक्त करने की नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत् अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-</p> <p>1-सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि (अपर जिलाधिकारी से अनिम्न हो) -अध्यक्ष</p> <p>2-सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी -सदस्य</p> <p>3-सम्बन्धित ऋण प्रदाता बैंक के प्रबन्धक-</p>

	<p>परन्तु सम्बन्धित उद्यमी द्वारा यदि व्यवसायिक उत्पादन को प्रारम्भ करने की तिथि से तीन वर्षों के अन्दर इकाई को बन्द कर दी जाती है, किराये पर दे दी जाती है अथवा लीज पर दे दी जाती है, ऐसी स्थिति में पूंजीगत अनुदान, ब्याज उपादान एवं अन्य रियायतों में अवमुक्त की गयी धनराशि ब्याज सहित नोडल विभाग (दुग्ध विकास विभाग) को वापस करनी होगी।</p> <p>उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगे।</p>	<p>सदस्य</p> <p>प्रोत्साहन का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन/उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद किया जायेगा। अनुदान की धनराशि अप्रैजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के टर्मलोन खाते में जमा किया जायेगा।</p> <p>परन्तु सम्बन्धित उद्यमी द्वारा इकाई को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से तीन वर्षों के अन्दर बन्द कर दिया जाता है, किराये पर दिया जाता है अथवा लीज पर दिया जाता है तो, ऐसी स्थिति में पूंजीगत अनुदान एवं अन्य रियायतों में अवमुक्त की गयी धनराशि ब्याज सहित नोडल विभाग (दुग्ध विकास विभाग) को वापस करनी होगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगे।</p>
18	<p>उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के लागू होने की तिथि तक वे इकाईयां, जिन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत विभिन्न अनुदान/रियायतें स्वीकृत की जा चुकी है, उन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के प्राविधानों के अनुसार अवशेष लाभ अनुमन्य होगा।</p>	<p>उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, अधिसूचना की तिथि से 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रख्यापन तिथि से पूर्व, दुग्ध विकास विभाग में तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल पर दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित, प्राप्त आवेदनों, जिनको उक्त कट आफ तिथि से पूर्व बैंक ऋण स्वीकृत हो चुका है, को उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान एवं रियायतें स्वीकृत की जायेगी।</p> <p>उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 (यथासंशोधित) के द्वितीय संशोधन की तिथि से पूर्व आनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो चुके पूर्ण परियोजना प्रस्तावों</p>

		के संबंध में अनुदान एवं रियायतों के लिए कार्यवाही नीति के पूर्व प्राविधानों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
19.3	----	कोई ऐसी इकाई जिसे किसी एक प्रोत्साहन श्रेणी के अन्तर्गत अनुदान मिला हो, को अनुदान स्वीकृत होने की तिथि से आगामी दो वर्षों की अवधि में उसी श्रेणी में आवेदन की अनुमति नहीं होगी।
19.4	----	एक इकाई एक ही परियोजना के लिए एक से अधिक प्रोत्साहन श्रेणियों में आवेदन कर सकती है, यदि वह संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पात्र हो।
19.5	----	बैंक/वित्तीय संस्था का अर्थ: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सरकारी नियंत्रण वाली वित्तीय संस्था, या RBI द्वारा अनुमोदित NBFC

3- उपर्युक्तानुसार शासनादेश संख्या-104/53-1-2023, दिनांक-20.02.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त दिशा-निर्देश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

( मुकेश कुमार मेश्राम )

अपर मुख्य सचिव

संख्या-59(1)/53-1-2026 एवं तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
- 8- सचिव, 30प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

- 10- प्रबंध निदेशक,पी0सी0डी0एफ0लि0,29 पार्क रोड,लखनऊ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 13- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 14- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
- 15- वेब मास्टर,दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन,लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(रामबूझ)

अनु सचिव।

I/277616/2023

संख्या: 104 / 53-1-2023

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,  
दुग्धशाला विकास, उ०प्र०,  
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-77/दुग्ध-9/नीति-2022/दिशा-निर्देश/2022-23, दिनांक-20 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय अनुदान एवं रियायतों से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-20.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या-03/2022/1050/53-1099 (099)/26/2022, दिनांक-17 अक्टूबर, 2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय अनुदान एवं रियायतों से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत हैं :-

1- नीति की अवधि

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, अधिसूचना संख्या-03/2022/1050/53-1099(099)/26/2022, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 की तिथि से पाँच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

2- प्रस्तावों की पात्रता

उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रभावी अवधि में स्थापित होने वाली इकाईयों इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान, रियायतों व सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगी।

3- कार्य क्षेत्र

“उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022” सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

4- पात्र संस्थाएँ

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत दुग्ध उद्योगों की स्थापना के लिये निम्न संस्थाएँ पात्र होंगी :-

- (i) फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (Farmer Producers Organization)।
- (ii) मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनियों (Milk Producers Companies)।
- (iii) प्रदेश की सहकारी संस्थाएँ (Co-operative Institutions of the State)।
- (iv) निजी क्षेत्र के उद्यमी (Enterprenurs of private sector)।

## 5-पात्र सेक्टर

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत विभिन्न एफ0पी0ओ0 (Farmer Producer's Organization), एम0पी0सी0 (Milk Producer's Companies), प्रदेश की सहकारी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा निम्न क्षेत्र में उद्योग की स्थापना कर नीति में प्राविधानित वित्तीय अनुदान/रियायतें सम्बन्धी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

- (i) नवीन (Greenfield) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना।
- (ii) विद्यमान दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई (Brownfield) की क्षमता का विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)।
- (iii) गौवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं हेतु नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई (Cattle Feed & Cattle Nutritional Products Manufacturing Unit) की स्थापना अथवा विद्यमान पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की क्षमता विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)।
- (iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना।
- (v) नवीन डेयरी तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी यथा ट्रेसिबिलिटी (Traceability) के उपकरणों एवं सहवर्ती साफ्टवेयर जैसे स्काडा (SCADA) सिस्टम की स्थापना।
- (vi) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु दुग्ध अवशीतन केन्द्र (Milk Chilling Center) के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन/कूलिंग वैन/रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली इत्यादि का क्रय।

## 6- पात्र/अपात्र घटक

क्र0सं0	विवरण	पात्र घटक	अपात्र घटक
1	तकनीकी सिविल कार्य	उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित्त समस्त तकनीकी सिविल कार्य।	सिविल कार्य से सम्बन्धित वे सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बन्धित नहीं हैं, अपात्र घटक में शामिल किये जायेंगे, जिनका विवरण निम्नवत है:- (1) चहारदीवारी। (2) सम्पर्क मार्ग। (3) प्रशासनिक कार्यालय भवन। (4) प्रसाधन कक्ष। (5) श्रमिक विश्राम गृह और श्रमिकों हेतु क्वाटर्स। (6) सफाई कक्ष। (7) सिक्योरिटी गार्ड कक्ष। (8) सभाकक्ष निर्माण। (9) निर्माण से सम्बन्धित परामर्श शुल्क।
2	मशीनरी	उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद की समस्त प्रक्रियाओं से सम्बन्धित उपकरण एवं मशीनरी पात्र घटक के अन्तर्गत आयेंगे। उदाहरणार्थ- क-दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित- (1) आटोमेशन, मिक्सिंग, सेपरेशन, स्टैन्डर्डाइजेशन, शुगर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एण्ड सेनेटाइजेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लैरिफिकेशन, फोर्टीफॉइंग आदि। (2) पाश्चुराइजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, ड्राइंग, स्टरलाइजेशन, कन्सन्ट्रेशन आदि। (3) कैनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, लेबेलिंग, फिलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि। (4) फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि। (5) कन्ट्रोल टेम्पेचर, ट्रान्सपोर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।	प्लाण्ट एवं मशीनरी में निम्नलिखित को अपात्र घटक में शामिल किया जायेगा:- (1) ईंधन/तेल आदि उपभोग की वस्तुयें एवं भण्डार सामग्री। (2) कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण। (3) परिवहन वाहन। (4) उपयोग की गयी/पुरानी मशीनें/मरम्मत की हुई मशीनरी। (5) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और परिवहन शुल्क। (6) मशीनरी की पेंटिंग का व्यय। (7) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सम्बन्धित उपकरण। (8) सम्बन्धित परामर्श शुल्क। (9) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।

I/277616/2023

	<p>(6)प्लांट के अन्दर अन्य समस्त प्रसंस्करण/परीक्षण/यातायात/भण्डार सुविधाएं जो कि मूल्य संवर्धन एवं शेल्फ लाईफ बढ़ाने से सम्बन्धित हों, पात्र होंगे।</p> <p>ख-पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद से सम्बन्धित-पेलेट मिल, मिक्सर, शीरा भंडारण टैंक, बॉयलर, कन्वेयर सिस्टम, स्काडा आधारित स्वचालन, अनाज भंडारण साइलो आदि के साथ पशु आहार निर्माण से सम्बन्धित निर्माण संयंत्र आदि पात्र होंगे।</p> <p>ग- तकनीकी उन्नयन-तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।</p> <p>घ-ट्रेसबिलिटी एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण-ट्रेसबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) इत्यादि पात्र होंगे।</p> <p>ड.-कोल्ड चेन की स्थापना- रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि से सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।</p>	
--	---	--

7-प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं सुविधाएं निम्नवत् होंगी:-

#### 7.1 पूंजीगत निवेश अनुदान

प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

#### 7.2 ब्याज उपादान

##### (क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 10.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

##### (ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना

नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 7.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

##### (ग) दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन

विद्यमान डेयरी प्लान्ट में तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

##### (घ) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी

डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

##### (ड.) कोल्ड चेन की स्थापना

रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

##### (च) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(छ) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ज) मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे:-चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

7.3-बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायी जायेंगी-

- (i) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत, जो रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 03 वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान देय होगा।
- (ii) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु जलयान/वायुयान से प्रेषण हेतु उत्पाद की एफ0ओ0बी0 (Freight on Board) मूल्य का 20 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 40 लाख प्रतिवर्ष की दर से 03 वर्षों तक अनुदान देय होगा।
- (iii) प्रदेश में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रति लाभार्थी अनुमन्य होगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश में एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

7.4-मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एकीडिटेशन जैसे आई0एस0ओ0-14001, आई0एस0ओ0-22000, एच0ए0सी0पी0 तथा सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेशन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस और टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.0 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। मानकीकरण प्रोत्साहन नीति की अवधि में प्रमाणन/पंजीकरण के आधार पर दिया जाएगा।

7.5-पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाईयों द्वारा पेटेण्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.0 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी। यह प्रोत्साहन नीति की अवधि में पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण के आधार पर दिया जाएगा।

7.6-विद्युत शुल्क

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी।

I/277616/2023

## 7.7-स्टाम्प शुल्क

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का आंकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

8- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रस्तावों की पात्रता के निर्धारण में प्रथम आवक व प्रथम पावक के सिद्धान्त को उक्त नीति के प्रस्तर-03 में उल्लिखित क्षेत्रवार/श्रेणीवार ध्यान में रखा जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाय। 'पहली' परियोजनाएं वे होंगी जिन्हें नीति और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार अनुदान/प्रोत्साहनों की मंजूरी के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद किया जाएगा।

## 9-डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर

(i) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना शासन से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त मुख्यालय स्तर पर दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर विषय विशेषज्ञों, डोमेन एक्सपर्ट्स के सहयोग से संचालित किया जायेगा तथा जिला एवं राज्य स्तर पर उद्योगबन्धु/निवेश मित्र आदि सुसंगत पोर्टलों से इन्टीग्रेटेड रहेगा। इस सेन्टर द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन पत्रों की पत्रावली तैयार कर, उनका परीक्षण एवं मूल्यांकन करते हुये प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित दुग्ध आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्री-अप्रेजल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगे।

## 10-आवेदन तथा आवेदन पत्र की प्राप्ति

इस नीति के अन्तर्गत समस्त आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में किये जायेंगे। आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदनों का डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण कर तत्काल आवेदक को वांछित सूचनाएं यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु संसूचित किया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के परीक्षण, मूल्यांकन, स्वीकृति एवं पूंजीगत अनुदान/ब्याज उपादान/विभिन्न रियायतों की स्वीकृति की समयसीमा का निर्धारण एक्टिविटी प्लान चार्ट (अनुलग्नक-3) में उल्लिखित है।

## 11-नीति के अन्तर्गत विस्तारित/तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित आवेदन किये जाने पर संस्थान/प्लांट का पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए तथा दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) एवं दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना आवेदक/संस्था द्वारा विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

विस्तारीकरण/तकनीकी उन्नयन के प्रकरण में पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन कराये जाने हेतु विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) के निम्नवत अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-

1- सम्बन्धित मण्डल के दुग्धशाला विकास अधिकारी

— अध्यक्ष

- |    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
| 2- | सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी | - | सदस्य |
| 3- | सम्बन्धित आवेदक/संस्था के प्रतिनिधि          | - | सदस्य |

### 12-पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदन

(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला की स्थापना से सम्बन्धित इकाईयों, पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासंभव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व करेंगे। पूँजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेकजर-ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित इकाईयों को पूँजीगत अनुदान के लिए अपना आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा पूँजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेकजर-ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन प्रस्तर-11 में प्राविधानित विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

### 12.1 ब्याज उपादान हेतु आवेदन

(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना, नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना, दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी की स्थापना, कोल्ड चैन की स्थापना तथा मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासंभव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व किये जायेंगे। ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेकजर-बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित इकाईयों द्वारा आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेकजर-बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन की स्थापना से पूर्व सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

(iii) कोल्ड चैन की स्थापना हेतु ब्याज उपादान प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेकजर-बी/एनेकजर-बीबी) (जो लागू हो) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1/अनुलग्नक-2 में उल्लिखित है।

### 12.2 प्रोत्साहन प्राविधान हेतु आवेदन

मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन, विद्युत शुल्क (ड्यूटी), स्टाम्प शुल्क तथा मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण कराये जाने सम्बन्धी आवेदन इकाई के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। बाजार

I/277616/2023

विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन के अन्तर्गत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक इकाई को केवल एक देश में एक नमूना (सैंपल) प्रेषित करने तक अनुदान उपलब्ध होगा। प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेकजर-एए एवं एनेकजर-एबी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-2 में उल्लिखित है।

13-नीति के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त किये जाने से पूर्व संस्थान का भौतिक/स्थलीय सत्यापन सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुदान/वित्तीय सहायता का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने, समस्त वांछित अभिलेख प्राप्त होने तथा संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) का भौतिक/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता अवमुक्त करने की नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत् अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1-सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि (अपर जिलाधिकारी से अनिम्न हो) | - | अध्यक्ष |
| 2-सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी                               | - | सदस्य   |
| 3-सम्बन्धित ऋण प्रदाता बैंक के प्रबन्धक                                   | - | सदस्य   |

प्रोत्साहन का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन/उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद किया जायेगा। अनुदान की धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के टर्मलोन खाते में जमा किया जायेगा।

परन्तु सम्बन्धित उद्यमी द्वारा यदि व्यवसायिक उत्पादन को प्रारम्भ करने की तिथि से तीन वर्षों के अन्दर इकाई को बन्द कर दी जाती है, किराये पर दे दी जाती है अथवा लीज पर दे दी जाती है, ऐसी स्थिति में पूँजीगत अनुदान, ब्याज उपादान एवं अन्य रियायतों में अवमुक्त की गयी धनराशि ब्याज सहित नोडल विभाग (दुग्ध विकास विभाग) को वापस करनी होगी।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगे।

14-उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का अनुदान एवं वित्तीय प्रोत्साहन हेतु मूल्यांकन एवं परीक्षण का कार्य

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान, ब्याज उपादान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन, मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्रोत्साहन, विद्युत अधिभार तथा स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर द्वारा मूल्यांकन एवं परीक्षण करते हुये मुख्यालय (दुग्ध आयुक्त कार्यालय) स्तर पर गठित प्री-अप्रेजल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

15-दुग्ध नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

15.1-राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति गठित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। सुसंगत विभागों के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सहकारिता से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योगों के प्रतिनिधि एवं तकनीकी विशेषज्ञ भी इस समिति के सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन इसके सदस्य-सचिव होंगे।

15.2-प्रशासकीय विभाग स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति

इस नीति के अन्तर्गत शासन स्तर पर प्री-अप्रेजल समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्रभारी सचिव, दुग्ध विकास विभाग की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण, तकनीकी विशेषज्ञ, वित्त-विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे एवं दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

15.3-मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री-अप्रेजल समिति

I/277616/2023

इस नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० की अध्यक्षता में प्री-अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। इसमें दुग्धशाला विकास विभाग के अन्य अधिकारीगण, वित्त नियन्त्रक एवं तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य तथा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला विकास अधिकारी (दुग्ध नीति) सदस्य-सचिव होंगे।

#### 15.4—जनपद स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

इस नीति के अंतर्गत किये जा रहे क्रियाकलापों का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा उद्योगबंधु के माध्यम से किया जायेगा। इस कार्य हेतु उद्योगबंधु की समिति में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी भी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे।

#### 16—नोडल विभाग

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए दुग्ध विकास विभाग, नोडल विभाग होगा।

#### 17—दुग्ध नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नवीन नीति के प्रचार-प्रसार हेतु नोडल संस्था द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:—

- (i) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न प्रोत्साहनों का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- (ii) प्रदेश में उद्योगों हेतु विद्यमान आकर्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग।
- (iii) नीति के प्रचार-प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रोड शो तथा अन्य इवेंट्स का आयोजन।

18— उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के लागू होने की तिथि तक वे इकाईयां, जिन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत विभिन्न अनुदान/रियायतें स्वीकृत की जा चुकी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के प्राविधानों के अनुसार अवशेष लाभ अनुमन्य होगा।

#### 19—विविध

19.1 उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों व अनुलग्नक में किसी बिन्दु पर तार्किक कठिनाई होने पर उसका समाधान करने हेतु प्रशासकीय विभाग/दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र० शासन सक्षम होगा।

19.2 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

#### संलग्नक—यथोक्त

भवदीय

Signed by डा० रजनीश दुबे

(Date: 20/02/2023) 13:29:58

अपर मुख्य सचिव।  
Reason: Approved

I/277616/2023

संख्या-104(1)/53-1-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
- 8- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 13- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 14- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
- 15- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(पंकज कुमार सिंह)

अनु सचिव।